कबाड़ जमा करना लाखों के लिये रोजगार है पर मोदी सरकार का 'बही-खाता' बस उन्हें जीएसटी जमा करने का स्त्रोत मानता है

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट

कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले की हांक करता सलीम रोज सुबह फरीदाबाद के पुराने बसे हुडा सेक्टरों में अपने रिक्शे से दुआ सलाम करता निकलता है। इस दुआ सलाम के पीछे सलीम का रोजी-रोटी का स्वार्थ निहित है और वो ये कि घरों का प्लास्टिक कचरा और अखबार अधिक मात्रा में मिल जाए तो दिन अच्छा बीत जाए।

31 वर्षीय सलीम बुलंदशहर से फरीदाबाद लकड़ी का काम करने आये थे। सलीम के मामू जान खुद एक बढ़ई हैं और बहुत कम उम्र से ही उन्होंने सलीम को बढ़ईगिरी में उस्तादी दिलवा दी थी। सलीम ने बताया कि शुरू-शुरू में नोएडा आये क्योंकि घरों और मकानों में सभी को लकड़ी का काम करवाना होता था तो पहले तो काम खूब मिला। पर अब वक्त ऐसा आ गया है कि लकड़ी का काम तो बिल्कुल ही नहीं रहा बाजार में। इसका क्या कारण है? सलीम के अनुसार, अब लोग मकान नहीं बना या खरीद रहे वैसे जैसे आज से 7-8 साल पहले बना या खरीद रहे थे। इन सीमाओं के चलते सलीम ने घर वापस जाने की बजाय कबाड़ी के काम में हाथ डालने की सोची।

कबाड़ के काम में ऐसा क्या है जिसके लिए सलीम ने बढ़ईगिरी को लगभग न कह दिया। सलीम ने कहा कि कुछ नहीं, सिवाय उम्मीद के। मतलब कि लकड़ी के काम के लिए दिन भर इंतजार करो और कोई याद करे तो चलें काम करने; पर कबाड़ के काम का दायरा बड़ा है। झोले से अपना तराजू और बाट निकालते हुए सलीम ने बताया कि अपने रिश्तेदारों को कबाड़ से अच्छा जीवन जीते देखा था तो सोचा चलो यही सही। पर जब तक सलीम ने इस धंधे में कदम रखा ये भी मंदा हो गया। इसके मंदे होने के पीछे भी लोगों की जेब में पैसा न होना ही एकमात्र कारण रहा। नोटबंदी ने तो कमर ही तोड़ दी।

पहले जब पैसा था तो लोग घर में सफेदी रंगाई पुताई ये सब काम त्योहारों पर करवाया करते थे, घर टूटते थे और बनते थे। इन्ही मलबों में निकला लोहा पिघल कर सलीम जैसे गरीबों की रगों में लहू बनाता था, बेशक उस खून में आयरन की मात्रा न हो पर ठेला खींचने भर का कैल्शियम मिल जाता था। आज न तो लोग उस स्तर पर घर बनवा रहे हैं न रेनोवेशन का काम हो रहा है। मंदी से तंग होकर सलीम ने ठेले पर घूम-घूम कर कबाड़ इकट्ठा करने का फैसला किया और अब एक साल से वो फरीदाबाद के सेक्टरों में अखबार और अन्य रद्दी खरीद रहा है।

इतनी जानकारी देने के बदले सलीम ने कहा कि बाबूजी अब कुछ रद्दी भी दे दो या टिन टब्बर। अखबार का ढेर सलीम के सामने रखने के बाद याद आया कि शाम की अपनी थकान मिटाने वाली बीयर की खाली बोतलें भी तो इस कबाड़ी वाले की रात की भूख मिटा सकती हैं, सो 25 बीयर की बोतले सलीम के सामने रख दीं। बड़ी ही बेरुखी से बोतलों को देखते हुए सलीम ने कहा कि इनका क्या करूँगा? कोई नहीं लेता ये अब। एक वक्त था जब इनकी डिमांड थी पर अब तो इनको लेना घाटे का सौदा है। ऊपर से अगर लाने-लेजाने में कोई बोतल टूट गई तो उसका नुकसान अलग। खैर 70 रुपये रद्दी का देकर सलीम ने विदा ली।

सलीम के जाते ही एक अन्य कबाड़ी वाले ने सलाम के साथ रद्दी देने का आग्रह किया। रद्दी तो नहीं है पर जो कुछ सलीम ने बताया मैंने उसकी पुष्टि के लिए 45 वर्षीय मिंटू से उनके 5 मिनट मांग लिए। सेक्टर 9 के एक घर से थोड़ा सा टिन ले जाते मिंटू से पूछा कि वो माल कहां बेचेंगे तो उसने बड़े हास्यास्पद तरीके से बताया कि भई नंगा नहाये क्या निचोड़े क्या? इतने को लेकर कहा जाऊंगा? किसी दूसरे कबाड़ वाले को देकर देसी मारूंगा आज। सुबह से सिर्फ ये मिला है वरना एक वक्त था जब सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। हमसे बेहतर पल्लेदार हैं जो अब भी कुछ पा जाते हैं।

विस्तार से पूछने पर मिंटू ने बताया कि पहले दीवाली पर लोग नए घर खरीदते थे तो वो तो अब इस सरकार में हो नहीं रहा। सबसे बड़ा काम उनका लोगों द्वारा घरों की मरम्मत कराने से चलता था, जिसमें ढेरों मलबा निकलता था। अब लोग खुद कमाई को तरस रहे हैं तो घर की क्या रंग-रोगन और मरम्मत करेंगे। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है कबाड़ वो भी अब काम का नहीं रहा क्योंकि सरकार ने कबाड़ आइटम पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया। इतना टैक्स देकर कबाड़ में छोटा कबाड़ी क्या कमायेगा? बोतलों के बारे में पूछने पर मिंटू ने बताया कि सलीम की जानकारी लगभग सही है। कांच की बोतलों को लेने के आजकल कम ही कबाड़ी इच्छुक हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि पहले जब कांच की बोतल इकट्ठी होती थी तो वही कंपनी जिनके मार्के की बोतलें थी इनको कबाड़ियों से वापस ले लिया करती थी। पर अब कंपनी इनको वापस लेने की बजाय नयी बोतल बनाने में ज्यादा रुचि रखती है।

फरीदाबाद बाईपास पर अवैध रूप से स्क्रैप रखने का अड्डा बनाए छोटे बीरीछपाल, सलीम और मिंटू जैसे घर-घर से कबाड़ लेने वालों से उनका माल लेकर आगे बड़े कबाडियों को भेज देते हैं। बीरीछपाल ने बताया कि 24 साल के अपने अनुभव से उनको ये समझ में आया है कि कचरा आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है बशर्ते सरकार भी थोड़ी मदद करे तो। और अगर मदद न भी करे तो कम से कम रास्ते में रोड़े न पैदा करे।

स्वरोजगार पर सरकार की मार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कचरे संबंधी नियमों का पालन होता है। चीन ने अपने यहाँ ई-कचरे के आयात पर रोक कुछ महीने पहले ही लगाई है। हांगकांग में बैटरियाँ व केथोड रे ट्यूब का आयात नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, जापान व ताईवान ने यह नियम बनाया है कि जो भी कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती हैं वे अपने वार्षिक उत्पादन का 75 प्रतिशत रिसाइकल करें। वहीं भारत की बात की जाए तो अभी ई-कचरे के निपटान व रिसाइकलिंग के लिए कोई प्रयास ही शुरू नहीं हुए। देश में तेजी से बढ़ रही कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या से भी अब इस तरह के नियम-कायदे बनाना जरूरी हो गया है। सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को इस खतरे से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए पर अभी ये विभाग भी सरकार की तारीफों में व्यस्त है।

तामिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों को ई-कचरे के निस्तारण के लिए उचित तरीके अपनाए जाने की हिदायत दी है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसका पालन नहीं कर रही हैं। इंडो-जर्मन स्विस ई-वेस्ट कंपनी के सहयोग से बंगलौर में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन ''ई-वेस्ट एजेंसी'' ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सही निपटान के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी पत्र लिखा है, कहा है कि इसके संबंध में कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए।

भारत का खुद का ई-कचरा निस्तारण गले की फांस है जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन ''ग्रीनपीस'' के एक अध्ययन के अनुसार 49 देशों से इस तरह का कचरा भारत में आयात होता है। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गाती फिर रही है कि बेसल नियमों के तहत हम सभी प्रावधान करते हैं जिसमे कचरा निस्तारण हो। वहीं पेरिस समझौतों में फोटो खिंचवाने में बेशक कोई कसर नहीं रख छोड़ते हमारे प्रधानमंत्री; पर असल में कचरे का बोझ भारतमाता अपने सीने में लेकर मर रही है और उसे एवं खुद को बचाने की एक बड़ी कोशिश संजू और अकील जैसे स्व-रोजगारी लोग कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता।

कांच की बोतलों पर बात करते हुए पाल ने बताया कि मिंटू की बात आंशिक रूप से ठीक है पर ऐसा नहीं है कि अब कांच की बोतल को लेना ही बंद कर दिया है। हां ये जरूर है कि कंपनी अब नयी बोतल बनाने में अधिक रुचि रखती है क्योंकि इन बोतलों को स्क्रैप डीलर से गुजरते हुए इतने बिचौलिये शामिल हो जाते हैं कि जितने की बोतल कंपनी वापस लेगी उससे कम में नयी बोतल बना लेगी। तो फिर कंपनी को अपना मुनाफा चाहिए न कि पर्यावरण और हमारी जैसों की जिन्दगी की सहूलियत को देखना।

पाल जैसे ही न जाने कितने और पाल हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी के कचरे को अपनी जिन्दगी बनाये बैठे हैं। पर सारा कचरा इनके काम का नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम में कचरा ढोने की गाड़ी को चलाने वाले 28 वर्षीय गुरचरन ने बताया कि कचरा भी अपने साथ तरह-तरह के रोजगार पैदा करता है और साथ ही भ्रष्टाचार भी, पर कैसे? ये जानने के लिए गुरचरन ने हमारी मुलाकात दिल्ली-फरीदाबाद बॉर्डर पर कचरा बीनने वाले दो लड़कों संजू और अकील से करवाई। स्कूल जाने की उम्र में ये दोनों लड़के गंदे नालों और बजबजाती गलियों की खाक छानते फिरते हैं। संजू ने बताया कि वो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करते हैं और अकील कागज या फिर जो भी काम का मिल जाए सड़क पर। सलीम जैसा ठेला तो नहीं है पर सफेद प्लास्टिक की दो बोरियों को जोड़ कर झोला बना लेना ऐसे बीनने वालों के बाएं हाथ का काम है। इस थैले में मोदी के सपने को सच करने की जो कूवत है वो शायद न पर्यावरण मंत्री के बस की बात है और न ही खुद प्रधानमंत्री मोदी के।

अकील और संजू बेशक देखने में स्लमडॉग जैसे थे पर उनकी अक्लमंदी का सानी फिलहाल संसद में भी शायद नहीं है। 18 वर्ष के दो बच्चों ने सारे कचरे निस्तारण और रोजगार के मोडल को उँगलियों पर गिना दिया। अकील ने बताया कि जो कचरा वो और संजू मिलकर इकट्ठा करते हैं उसके कई रूप हैं। पहला ये कि सूखा और गीला। इसमें गुरचरण ने जोड़ते हुए बताया कि सरकारी स्कीम के तहत कचरा उठाने वाली कम्पनी और घर के लोग अपने कचरे को अलग-अलग थैलों में सूखे और गीले के रूप में दें। ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ कागजों और बातों तक की नीति है। रिसायकिल होने वाले कचरे को तो संजू और अकील कबाड़ी वालों तक पंहुचा देते हैं और बाकी का कचरा गुरचरण जैसे ड्राइवर बंदवाड़ी जैसे लैंडफिल साइटों पर फेंक आते हैं। अकील ने बताया कि रविवार के दिन हम दोनों लैंडफिल पर जाते हैं पर ताकि ई-कचरा बीन सकें, पर ज्यादातर समय उन्हें पीट कर सरकारी कर्मचारी भगा देते हैं। जबकि काम हम उन्हीं कर्मचारियों का कर रहे होते हैं और वो खुद कोई काम नहीं करना चाहते। यही कर्मचारी जो पक्के हैं अपना काम हमसे शहरों में करवाते हैं और इसके बदले में 10-20 रुपये दे देते हैं। पर जब हम इनसे ई-कचरे को देने की गुहार लगाते हैं तो हमारी बजाय ये खुद उसे कबाड़ी वालों को बेचते हैं।

बीयर की बोतलों की क्या स्थिति है? अकील ने कहा कि पहले तो मैं खुद ठेके के आस-पास जहाँ लोग दारू पीते थे इन्ही खाली बोतलों के लालच में खड़ा रहता था पर अब इनकी डिमांड न जाने क्यों कम हो गई। पर ई-कचरे के लिए हम अब ज्यादा लालायित रहते हैं। इस कचरे को मोबाइल वाले कंप्यूटर वाले सब ले लेते हैं और आसानी से बिक भी जाता है। पर हम जैसे छोटे कचरा बीनने वालों को ये कचरा भीड़ में ढूंढना पड़ता है। जबकि बड़े दलाल सीधा सरकारी कर्मचारियों से सेटिंग करके या बड़ी कंपनियों में से इन्हें उठा लेते हैं।

हम बात को कांच की बोतलों पर लाना चाहते थे और ये दोनों इसे ई-कचरे में डालना चाहते थे। संजू ने कहा कि कांच की बोतल तब तक नहीं फायदेमंद हो सकती जब तक इसके लिए सरकार नियम न बना दे। नियम ये कि जिस कंपनी की बोतल बिकती है उसे उसी बोतल को किसी न किसी माध्यम से वापस लेकर फिर उसी में नयी पैकिंग करनी होगी। ठन्डे पेय पदार्थों के लिए ऐसा होता भी है। पर अब कम्पनियाँ सिर्फ प्लास्टिक बोतल में पेय बेचती हैं जिसे आसानी से दुकान में रखा जा सके और फिर पीने के बाद सड़क के किनारे फेका जा सके। और फिर नाला जाम हो तो अकील जैसों को उसमें घुसा दिया जाये।

अकील और संजू की बात बेशक ठहाका लगाने के बाद वहीँ समाप्त हो गई। पर जिस कचरे और ई-कचरे की दुहाई दिन रात विश्वपटल पर हो रही है उसका एक छोटा सा सामाधान इन बच्चों ने दिया। क्यों नहीं जो कम्पनियां बीयर और शराब का उत्पादन करती हैं उनको उसी माध्यम से बोतल वापस लेने के लिए नियम बनाये जाएं जिस माध्यम से वो ग्राहक तक पहुंचती हैं। दिल्ली और आस-पास का रिसायकिल होने वाला कचरा फिलहाल नांगलोई जैसी छोटी जगहों पर छंटनी के बाद कॉम्प्रेस करके मानेसर, रेवाड़ी और जयपुर तक रिसाइकिल होने जाता है।

सरकार इनके लिए न तो कारगर नियम बनाती है और न इस धंधे में जुड़े लोगों के लिए। हां सरकारी कर्मचारी जरूर मोटी तनख्वाह लेकर संजू और अकील जैसों को इस्तेमाल करते हैं। जबकि इन दोनों का कहना है कि हमे नौकरी न दो पर कचरा तो उठाने दो। मोदी जी के गाँधी के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने वाले शगूफे की मीयाद इस 2 अक्टूबर को पूरी हो रही है। जाहिर है फोटो का दौर चलेगा और पत्रकार अलग अलग एंगल से अपने कैमरामैन को फोटो लेने की हिदायत देगा। पर क्या कोई पत्रकार होगा जो कलम चला कर पूछे कि मोदी जी कौन सी रोजगार नीति के तहत भारत स्वच्छ हो गया?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06